गवर्नर – जनरल

1. बंगाल के गवर्नर-जनरल
- वॉरेन हेस्टिंग्स (1774–85)
- लार्ड कॉर्नवालिस (1786–93)
- सर जॉन शोर (1793–98)
- लॉर्ड वेलेजली (1798–1805)
- सरजॉर्ज बालों (1805–07)
- लॉर्ड मिंटो प्रथम (1807–13)
- लॉर्ड हेस्टिंग्स (1813–23)
- लॉर्ड एमहर्स्ट (1823–28)

2. भारत के गवर्नर जनरल
- लॉर्ड विलियम बेटिक (1828–35)
- चार्ल्स मेटफॉफ (1835–36)
- लॉर्ड ऑकलैंड (1836–42)
- लाई एलेनबरो (1842–44)
- लॉर्ड हार्डिंग (1844–48)
- लॉर्ड डलहौजी (1848–56)

3. Viceroys of India
- लॉर्ड कैनिंग (1856–62)
- लॉर्ड एल्गिन-I (1862–63)
- लॉर्ड लारेंस (1864–69)
- लॉर्ड मेयो (1869–72)
- लॉर्ड नार्थब्रुक (1872–76)
- लॉर्ड लिटन (1876–80)
- लॉर्ड रिपन (1880–84)
- लॉर्ड डफरिन (1884–88)
- लॉर्ड लैन्स डाउन (1888–94)
- लॉर्ड एल्गिन II (1894–99)
- लॉर्ड कर्जन (1899–05)
- लॉर्ड मिंटो-II (1905–10)
- लॉर्ड हार्डिंग II (1910–16)
- लॉर्ड चेम्सफोर्ड (1916–21)
- लॉर्ड रीडिंग (1921–26)
- लॉर्ड इरविन (1926–31)
- लॉर्ड वेलिंगडन (1931–36)
- लॉर्ड लिनलिथगो (1936–43)
- लॉर्ड वेवेल (1943–47)
- लॉर्ट माउण्टबेटन (1947–48)

बंगाल के गवर्नर

राबर्ट क्लाइव (1757-60 ई. एवं पुनः 1765-67 ई.) → बंगाल का प्रथम गवर्नर (1758)

1. इलाहाबाद की संधि (1765)
- बंगाल में द्वैध शासन
- मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को कम्पनी के संरक्षण में ले लिया।

2. दो उप-दीवान
- बंगाल — मुहम्मद रजा खाँ
- बिहार — राजा शिताब राय

3. अन्य गवर्नर → बरेलास्ट (1767-69), कार्टियर (1769-72), वारेन हेस्टिंग्स (1772-74)

4. रेग्यूलेटिंग एक्ट 1773 → बंगाल के गवर्नर → बंगाल का गवर्नर जेनरल → कार्यकाल 5 वर्षों

5. 1744 → BEIC का लिपिक

6. 1757 → प्लासी में नेतृत्व

7. 1758 → बंगाल का प्रथम गवर्नर

8. मुख्य कार्य व घटनाएं:- स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक
- कर्मचारियो हेतु अनुबंधित सेवा: धन व उपहार नहीं
- उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों के लिए एक अनुबंधित सिविल सेवा स्थापित की, जिसमें धन, पारितोषिक एवं उपहार स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाया गया।.
- व्यापार समिति (1765): नमक, सुपारी और तंबाकू का व्यापार
- क्लाइव फंड
- श्वेत विद्रोह (1766): फ्लेचर के नेतृत्व में सैन्य अधिकारियो का विद्रोह
- 1773 में महाभियोग

9. मृत्यु: 1774 में आत्महत्या

1. स्मिथ - "मानव जाति का नेता"
2. चौथम - "फ्रेडरिक महान से तुलना"
3. स्पीयर - "भारत में अंग्रेजी संप्रभुता का अग्रगामी"
4. कर्जन - " मार्लबरो व टूरेन से तुलना"

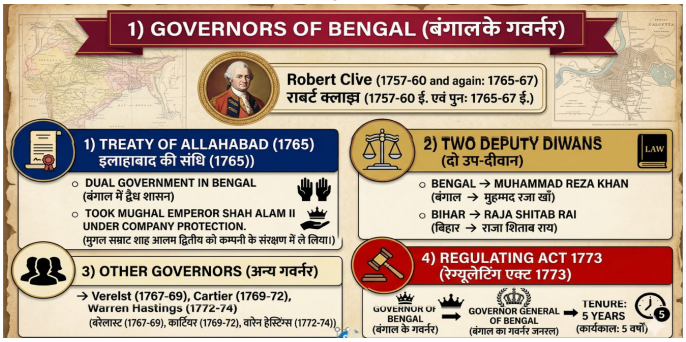

बंगाल के गवर्नर-जनरल

वारेन हेस्टिंग्स: 1774-85

1. उन्होंने क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया।
2. राजकीय कोषागार → मुर्शिदाबाद से कलकत्ता
   - 1772 → कलकत्ता में एक 'बोर्ड ऑफ रेवेन्यू'
3. 1772 → भू-राजस्व पद्धति → इजारेदारी प्रथा
   - जमीन का मालिकाना हक नहीं, बल्कि लगान वसूल करने का अधिकार उस व्यक्ति (इजारेदार) को दिया जाता था जो सबसे अधिक बोली लगाता
   - पंचसाला बंदोबस्त — शुरुआत में 5 वर्षों के लिए
   - 1777 → सालाना (1 वर्ष).
4. पिट्ट इंडिया: 1784
   - कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक-दूसरे से अलग
   - बोर्ड ऑफ कंट्रोल → कंपनी के राजनीतिक, नागरिक, सैन्य और राजस्व
5. 1774 → कलकत्ता मे एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना
   - अधिकार क्षेत्र → कलकत्ता (कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी जब दोनों पक्ष सहमत हों।)
   - **अंग्रेजी कानून**
   - मुख्य न्यायाधीश → एलिजा इम्पे (1782 में इस्तीफा).
   - हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फाँसी की सजा दिलवा दी थी।

- 1772 → प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना की

6. युद्ध: सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति
   - प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध (1775-1782) → सलबाई की संधि (1782)
   - द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध (1780-1784) → मंगलोर की संधि (1784)
7. एन.बी. हालहेड (1776) → मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद → ए कोड ऑफ जेन्टू लॉज
8. भगवद्गीता (1785) → चार्ल्स विल्किन्स
   - वारेन हेस्टिंग्स : प्रस्तावना
9. अभिज्ञान शाकुंतलम् → सर विलियम जोन्स
   - 1784 : 'एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल'
   - 1804 : बंबई में एशियाटिक सोसाइटी
   - 1823 : लंदन में एशियाटिक सोसाइटी
10. वारेन हेस्टिंग्स (1781) → कलकत्ता में मदरसा
    - मुगल सम्राट् को मिलने वाला 26 लाख रुपये की वार्षिक पेंशन बन्द
11. जोनाथन डंकन (1791) → बनारस में संस्कृत विद्यालय
12. भारत का पहला समाचार-पत्र (29 जनवरी 1780) → जेम्स हिक्की ने कलकत्ता से 'द बंगाल गजट' प्रकाशित किया।
13. जेम्स ग्रांट → मुगल साम्राज्य के ऐतिहासिक खंड
    - बंगाल के राजस्व पर गहन शोध
14. प्रस्थान → फरवरी 1785
    - ब्रिटिश संसद एडमंड बर्क ने हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया (1788–1795)
      - नंद कुमार की 'न्यायिक हत्या'।
      - रोहिल्ला युद्ध में अनैतिक हस्तक्षेप।
      - बनारस के राजा चैत सिंह के साथ दुर्व्यवहार
      - अवध की बेगमों से जबरन धन की वसूली
    - 1795 में 'हाउस ऑफ लॉर्ड्स' ने उन्हें सभी आरोपों से सम्मानपूर्वक बरी कर दिया

वॉरेन हेस्टिंग्स: ब्रिटिश बंगाल के शिल्पकार (1774–1785)

बंगाल के प्रथम गवर्नर-जनरल के रूप में, हेस्टिंग्स ने कंपनी के व्यापार से संगठित शासन व्यवस्था की ओर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का नेतृत्व किया। उन्होंने औपचारिक न्यायिक प्रणाली की स्थापना की तथा भारतीय शास्त्रीय अध्ययन को संरक्षण दिया, जिसका अंत एक चर्चित कानूनी मुकदमे में हुआ।

1772–1780: प्रशासनिक एवं न्यायिक आधार

शक्ति एवं राजस्व का केंद्रीकरण

"द्वैध शासन प्रणाली (Dyarchy)" को समाप्त किया तथा शाही कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया। मुर्शिदाबाद → कलकत्ता

इजारेदारी राजस्व प्रणाली

भूमि राजस्व वसूली के अधिकार निश्चित अवधि के लिए उच्चतम बोली लगाने वालों को नीलाम किए गए।

सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना (1774)

कलकत्ता में अंग्रेजी कानून के अंतर्गत एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके प्रमुख एलिजा इम्पे थे।

1781–1795: सांस्कृतिक संरक्षण एवं विधिक पुनर्गठन

सांस्कृतिक एवं शैक्षिक पुनर्जागरण

1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की तथा भगवद्गीता के प्रथम अंग्रेजी अनुवाद की देखरेख की।

पिट्स इंडिया एक्ट (1784)

इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों को उसके राजनीतिक कार्यों से स्पष्ट रूप से अलग कर दिया।

1. व्यावसायिक गतिविधियाँ 2. राजनीतिक कार्य

सात वर्षीय महाभियोग मुकदमा

हेस्टिंग्स पर "न्यायिक हत्या" और जबरन वसूली के आरोप लगाए गए, किन्तु अंततः 1795 में उन्हें बरी कर दिया गया।

सैन्य संघर्ष एवं कूटनीतिक समाधान

संघर्ष	अवधि	अंतिम संधि
प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध	1775–1782	सालबाई की संधि (1782)
द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध	1780–1784	मंगलौर की संधि (1784)

लॉर्ड कॉर्नवालिस (1786-1793 और 1805)

1. कॉर्नवालिस कोड (1793) → शक्तियों के पृथक्कीकरण
   - कलेक्टर
     - न्यायिक और फौजदारी शक्तियाँ छीन ली
     - केवल राजस्व वसूलने तक सीमित
     - कार्यों की समीक्षा अदालत में की जा सकती थी
   - जिला दीवानी अदालतों में → 'जिला न्यायाधीश'
   - भ्रमणकारी अदालतें (चार सर्किट न्यायालय): कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना
   - वकीलों का विनियमन : वकीलों के लिए योग्यता व शुल्क निर्धारित किए गए।
2. जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया
3. भ्रष्टाचार रोकने के लिए → अधिकारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध और उनके वेतन में भारी वृद्धि
4. प्रशासन के सभी उच्च पदों का यूरोपीयकरण
   - भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊँचा पद नहीं दिया जाता था।
   - भारत में 'सिविल सेवा' की शुरुआत का श्रेय
5. स्थायी बन्दोबस्त 1793 → जमींदारों को भू-राजस्व का लगभग 90% (10/11 भाग) कम्पनी को तथा लगभग 10% (1/11 भाग) अपने पास रखना था।
   - योजना → जॉन शोर → अहस्तक्षेप की नीति
   - बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में
   - इसमें जमींदार भू-राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे
6. तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध (1790-1792) → श्रीरंगपट्टनम की संधि (1792).
7. लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805 में दोबारा भारत के गवर्नर-जनरल बनकर आए, लेकिन कुछ ही समय बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी समाधि (मकबरा) आज भी गाजीपुर में स्थित है।

विशेषताएँ	*स्थायी बंदोबस्त*	*रैयतवाड़ी*	*महालवाड़ी*
वर्ष	1793	1820	1822
किसने लागू किया	लॉर्ड कॉर्नवालिस	अलेक्ज़ेंडर रीड + थॉमस मनरो	होल्ट मैकेंज़ी
क्षेत्र	बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, मद्रास के उत्तरी जिले (लगभग 19%)	मद्रास व बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम, बर्मा (लगभग 51%)	उत्तर-पश्चिम प्रांत, पंजाब, गंगा घाटी, मध्य भारत (लगभग 30%)
भू-राजस्व	स्थायी रूप से निश्चित	समय-समय पर संशोधित	समय-समय पर संशोधित
राजस्व संग्रहकर्ता	ज़मींदार	रैयत (किसान)	ग्राम प्रधान
भूमि का मालिक	ज़मींदार	रैयत	ग्राम समुदाय
भूमि का सर्वेक्षण	सर्वेक्षण नहीं	सर्वेक्षित	सर्वेक्षित

सर जॉन शोर (1793-98)

1. अहस्तक्षेप की नीति
   - भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न
   - खुर्दा का युद्ध (1795) → निज़ाम अंग्रेजों का मित्र था, लेकिन शोर ने मराठों के खिलाफ उसकी कोई मदद नहीं की।
2. गवर्नर-जनरल बनने से पहले शोर 'राजस्व बोर्ड' के अध्यक्ष थे।
3. ब्रिटिश संसद ने 1793 का चार्टर एक्ट पारित किया।
4. कन्या शिशु हत्या पर रोक, 1795 → बंगाल नियम-21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या को सामान्य हत्या के समान ही गंभीर अपराध घोषित किया